महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात एवं मध्यप्रदेश का लोकप्रिय समाचार पत्र

RNI No. MAHHIN/2013/49425
डाक पंजीयन सं. MNW/251/2016-2018
e-paper : www.srushtiagronews.com

Posted at Malad NDPO Dated of Posting
4th to 5th for (1st to 15th issue)
18th to 19th for (16th to 30th issue)

ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

सृष्टि एग्रो

वर्ष -5 | अंक-3 | मुंबई, 1 से 15 मार्च 2017 | मूल्य - 2 रुपए | पृष्ठ - 8

50 बोरी आलू के मंडी में किसान को मिला एक रुपया

सड़कों पर आलू फेंक कर विरोध जताते किसान

इंदौर/ लखनऊ (विसं)। 50 कट्टे (यानी 25 कुंटल) आलू की कीमत एक रुपये सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी लेकिन ये सच है। मध्य प्रदेश इंदौर में एक किसान ने 50 कट्टे आलू मंडी पहुंचाया जहां उसकी कीमत 1175 रुपये लगी, लेकिन मंडी में 1174 रुपये खर्चा काटा गया और किसान को सिर्फ एक रुपया ही मिला। वहीं पंजाब में घाटे से परेशान किसान आलू को सड़कों पर फेंक रहे हैं। इंदौर के ईश्वरखेडी गाँव निवासी राजकुमार चौधरी (28) के पास 10 बीघा आलू था। 23 फरवरी को वह 50 बोरी आलू मंडी ले गए जहां 1000 रुपये गाड़ी का भाड़ा हो गया और बाकी 174 रुपये मंडी के अन्य खर्च हो गए, मंडी से उन्हें सिर्फ एक रुपया ही मिला। राजकुमार ने बताया, दो दिन पहले मैं 108 कट्टे और आलू लेकर मंडी पहुंचा तो मुझे अपनी जेब से 773 रुपये का खर्च देना पड़ा, इससे अच्छा है आलू खेत में सड़ जाए या फिर पंजाब की तरह सड़क पर फेंक दूं। मध्य प्रदेश से ज्यादा बदतर हालात पंजाब के हैं, यहां किसानों ने आलू को सड़कों पर फेंकना शुरु कर दिया। साहनी और भटिंडा इलाके में कई जगह किसानों ने सड़कों पर आलू फेंककर अपना विरोध जताया है। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) समेत दूसरे कई संगठन इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। भाकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह बाजवा बताया कि यही हालात रहे तो देश में विद्रोह हो जाएगा, किसान सड़क पर उतरेगा फिर सरकार हालात नहीं संभाल पाएगी। पिछले 10 दिनों में पंजाब और हरियाणा में 70 किसानों ने आत्महत्या की है। बठिंडा में पिता-पुत्र ने आलू के घाटे के चलते जान दी है। सरकार को चाहिए कि तुरंत सरकारी दाम पर आलू खरीद करवाए और आगे से गेहूं की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए, वर्ना लोग आलू बोना बंद कर देंगे। 5 मार्च को हम लोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें आलू अहम मुद्दा होगा। सबसे ज्यादा आलू उत्पादक राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही हालात हैं।

किसानों का आलू 200 रुपये कुंटल मांगा जा रहा है, जिसमें उनको हजारों रुपये प्रति बीघे का घाटा हो रहा है। हजारों किसानों का आलू खेतों से अभी खुदा नहीं है, जो खोद चुके हैं उन्हें कोल्ड स्टोर में रखने की जगह नहीं मिल रही है। लखनऊ और उसके आसपास फुटकर में आलू 20 रुपये का 3-4 किलो मिल रहा है। जबकि खेतों में किसानों से 200 रुपये कुंटल का भावदिया जा रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी खपत से कई गुना ज्यादा रोजाना आलू पहुंच रहा है। मौसम की मेहरबानी से इस बार आलू का उत्पादन कई गुना ज्यादा हुआ है लेकिन अब किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है। राजकुमार को अपने बाकी 108 बोरी आलू के बदले 773 रुपये जेब से देने पड़े।

नासिक से दौड़ेगी नई 'प्याज रेलगाड़ी'

सुरेश शर्मा

मुंबई। महाराष्ट्र के प्रमुख प्याज उत्पादक इलाके नासिक में इस बार लाल प्याज की बंपर फसल को देखते हुए रेलवे किसानों की मदद के लिए आगे आया है। रेलवे ने देश के दूसरे हिस्सों में प्याज की ढुलाई के लिए आज से एक और मालगाड़ी उपलब्ध कराई है। नई मालगाड़ी आने से प्याज की ढुलाई में 30 प्रतिशत का इजाफा होगा। ये मालगाड़ी मध्य रेलवे उपलब्ध करा रहा है। प्याज की ढुलाई में तीन मालगाड़ियां पहले से लगी हुई हैं। नासिक प्याज उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। देश में होने वाले कुल प्याज उत्पादन का 30 प्रतिशत उत्पादन नासिक में होता है। प्याज की बंपर पैदावार हुई है। इससे दाम गिर गए हैं। किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस साल प्याज की भारी पैदावार को देखते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नासिक से प्याज की आगे ढुलाई के लिए मालगाड़ी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इस बार प्याज की फसल पिछले साल के मुकाबले करीब दोगुनी है। अधिकारी के मुताबिक, रेलवे पिछले साल के मुकाबले पहले से ही 50 प्रतिशत अधिक मालगाड़ियां उपलब्ध करा रहा है। एक और मालगाड़ी उपलब्ध कराने से प्याज उठाव क्षमता 30 प्रतिशत और बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां से देश के उत्तरी, पूर्वी, उत्तर पूर्व और पूर्वी तटीय हिस्सों की मंडियों में प्याज भेजा जा रहा है। इससे किसानों के लिए मंडी का आकार व्यापक होगा और उनकी परेशानी काफी हद तक दूर होगी।

Hindchem Corproation

SUPPER POTASSIUM HUMATE SHINY FLAKES

ZINK EDTA

SEAWEED EXTRACT FLACKES

N.P.K. WATER SOLUBLE FERTILIZER

AMINO ACID

- AMINO+HUMIC SHINY BALLS
- FERROUS SULPHATE19%
- MAGNESIUM SULPHATE 9.6%
- FERROUS EDTA12%
- E.D.T.A. ACID
- CAMPHOR
- SODIUM BICARBONATE
- EDTA DISODIUM
- CITRIC ACID MONOHYDRATE
- MANGANESE SULPHATE 30.5%
- SULPHUR 90% -80WDG
- BORON 20%
- BRONOPOL 25%
- PHOSPHORIC ACID

We Welcome Your Valuable Inquiry
Tel. 022-66998360/61
Fax-022-66450908
Email id: mamta@hindchem.com
Mo. 9004744077

सम्पादकीय

कृषि क्षेत्र में उछाल की उम्मीद

कृषि मंत्रालय ने हाल में उत्पादन के जो अनुमान जारी किए हैं उनसे यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2016-17 में कृषि क्षेत्र में जोरदार उछाल आने की उम्मीद है। यह पिछले दो साल के रुझान से एकदम उलट है। उन दोनों वर्षों में सूखा पड़ा था। खाद्यान्न उत्पादन में आठ फीसदी से अधिक का इजाफा होने जबकि दालों में 35 फीसदी तथा तिलहन में 25 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान है। बागवानी और पशुपालन उत्पादों की बात करें तो उनमें भी इजाफा हुआ है। बागवानी उत्पादन ने लगातार पांचवे साल खाद्यान्न को पीछे छोड़ दिया है। दो निष्कर्ष स्पष्ट हैं। पहला, ये आंकड़े बताते हैं कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि का सांख्यिकी कार्यालय का 4.1 फीसदी का अनुमान बढ़कर 6 फीसदी हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे यह भी पता चलता है कि नोटबंदी ने कृषि क्षेत्र को उस कदर प्रभावित नहीं किया। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि किसानों को इसकी वजह से कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बहरहाल, प्रचुर फसल का कृषि जिंस की कीमतों, मुद्रास्फीति और कृषि आय पर पड़ने वाला असर इतना सीधा सपाट भी नहीं है। मुख्य अनाज को छोड़कर लगभग हर जिंस की कीमत में गिरावट ही आई है और उसने उत्पादकों के हितों को बुरी तरह प्रभावित किया है। दलहन के मामलों में ऐसा खासतौर पर देखने को मिला है। फिलहाल अधिकांश दलहन न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही हैं। ऐसे में उनकी खेती किसानों के लिए लाभ का धंधा नहीं रह गई है। सब्जियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी सुरक्षा भी हासिल नहीं है लेकिन उनकी कीमतों में भी इस हद तक गिरावट आई है जहां मुनाफा नदारद हो गया है। उदाहरण के लिए प्याज का कारोबार मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में ऐसी दर पर हो रहा है कि उसकी उत्पादन लागत तक नहीं निकल पा रही है। ऐसे में अगर किसान अगले मौसम में प्याज का रकबा कम कर दें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से कीमतों में भी इजाफा होगा। कुल मिलाकर अधिशेष उत्पादन के कारण कृषि जिंस की कीमतों में आने वाली गिरावट ने भले ही खाद्य मुद्रास्फीति कम की हो और जो रिजर्व बैंक के लिए राहत के दायरे में हो लेकिन इसके चलते किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में कोई मदद मिलती नहीं दिखती और परिणामस्वरूप कृषि वृद्धि अथवा खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में भी। इस बीच इसके चलते नीतियों को लेकर कुछ चिंता भी पैदा होती है। उदाहरण के लिए यह अजीब प्रतीत होता है कि सरकार कई कृषि जिंसों के आयात को जारी रखे हुए है जबकि उनके घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है और कीमत कम हुई है। दलहन का आयात 60 लाख टन का स्तर पार कर चुका है और अब भी जारी है जबकि आमतौर पर यह हर साल 30-40 लाख टन ही होता है। भारी मात्रा में गेहूं का भी आयात किया जा रहा है। हालांकि घरेलू उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। सरकार के पास भारी मात्रा में गेहूं का भंडार भी है। ऐसे में गेहूं के कमजोर दर पर बिकने की संभावना भी नहीं नकारी जा सकती है। एक माह के भीतर नई फसल बाजार में आने वाली है। इसके अलावा भी नीतिकार कुछ कृषि जिंसों के निर्यात को उदार बनाने के पक्ष में नहीं दिख रहे जबकि इससे कीमतों की गिरावट थामी जा सकती है। बुरी बात यह है कि प्रमुख कृषि उत्पादों के वायदा कारोबार पर रोक और कारोबारियों के स्टॉक रखने की सीमा तय किए जाने जैसे आपूर्ति में कमी के समय के आपातकालीन उपायों को अब तक जारी रखा गया है। ऐसे नियमों को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

अच्छे मानसून से टूटे अनाज पैदावार के सारे रिकॉर्ड

नई दिल्ली (विसं)। मानसून की अच्छी बारिश से अनाज की पैदावार में रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई है। इससे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही किसानों ने राहत महसूस की है। लगातार दो साल पड़े सूखे से हलकान किसानों की माली हालत में पर्याप्त सुधार होने की संभावना है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। चालू फसल वर्ष में अब तक की सर्वाधिक पैदावार हुई है। अच्छे मानसून से मिट्टी में पर्याप्त नमी होने का फायदा किसानों ने उठाया। उन्होंने रिकॉर्ड रकबे में फसलों की बुवाई की है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल फसल का उत्पादन 27.19 करोड़ टन होगा। देश के कृषि उत्पादन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।पिछले फसल वर्ष में उत्पादन का यह आंकड़ा 26.55 करोड़ टन था।

दलहन फसलों की पैदावार में वृद्धि: उत्पादन के आंकड़े में सबसे खास बात यह है कि देश में दलहन की भारी कमी को पूरा करने के लिए सरकार के प्रयासों को किसानों ने अपने खेतों में सफल कर दिखाया है। दलहन फसलों की पैदावार में अब तक की सर्वाधिक 35.54 फीसदी वृद्धि दर दर्ज की गई है। दालों की पैदावार 2.21 करोड टन होगी। इससे हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी। गरीब आबादी के लिए घटती प्रोटीन की उपलब्धता के संकट से निपटने में मदद मिलेगी। सरकार ने दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को पर्याप्त बीज, खाद और कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। किसानों को खेती के जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना और उन्नत बीजों के साथ संतुलित खादों की पूरी आपूर्ति जैसे कारगर उपाय किए गए। केंद्र सरकार के अधिकारियों व कृषि वैज्ञानिकों ने हर सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रायों के अधिकारियों से संपर्क बनाये रखा।

जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कीटों एवं रोगों का नियंत्रण

डॉ.ऋषिपाल प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक, जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला (कीट विज्ञान विभाग)
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय-मेरठ उ.प्र.पिन-250110

जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व भर में दूसरे पायदान पर आता है। यहां कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर अधिकांश जनसंख्या का जीवनयापन निर्भर है। कृषि फसलों के सफल उत्पादन में विभिन्न प्रकार की समस्यायें आती हैं जिनमें कीट एवं विभिन्न प्रकार की बीमारियां प्रमुख स्थान रखती हैं। एक तरफ बीमारियां पौधों कायिक अवस्था को प्रभावित कर उनकी वृद्धि एवं उत्पादन को प्रभावित करती हैं, तो कीट फसलों को खेतों से लेकर भण्डार गृह तक क्षतिग्रस्त कर सर्वाधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें अन्ततः उत्पाद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

विभिन्न रोगों एवं कीटों की रोकथाम के लिये जिन कृषि रसायनों का उपयोग होता है, वे विभिन्न प्रकार की समस्यायें जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव, द्वितीयक पेस्ट का प्रमुख पेस्ट में बदलना, कीटों का रसायनों के लिये प्रतिरोधी होना इत्यादि ,पैदा करते हैं। इन समस्याओं के कारण कीट एवं पादप रोग वैज्ञानिकों का ध्यान जैव प्रौद्योगिकी की ओर आकर्षित हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटरोधी एवं रोग प्रतिरोधी पौधों का विकास किया जा रहा है। उपरोक्त पौधों के विकास के लिये मुख्यतः मोलिकुलर बायलोजी एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग विद्या का इस्तेमाल किया जा रहा हैं। जैव प्रौद्योगिकी का विकास एवं पादप विज्ञान में उसका उपयोग करके विभिन्न फसलों के कीट एवं रोग प्रतिरोधी पौधे विकसित किये गये हैं।

उपरोक्त पौधे/प्रजातियां प्रचलित फसलों के अंदर एक या एक से अधिक बाहरी जीन समावेशित करके विकसित किये गये है। सन् 1994 में सर्वप्रथम पराजीनी फसलों की खेती की शुरूआत अमेरिका में हुई थी जिसके आसानजनक परिणाम प्राप्त होने पर पराजीनी फसलों को विश्वभर में विभिन्न देशों द्वारा अपनाया गया है। सन् 1996 में कपास की फसल के कीटरोधी पौधों का विकास हुआ था एवं विभिन्न स्तरों पर निगरानी एवं परीक्षणों के बाद सन् 2002 में पराजीनी कपास को खेती का व्यवसायिक स्तर पर उपयोग शुरू हुआ जो कि शुरूआत में लगभग 29,307 हैक्टेर (2002) या तथा 8 वर्षों में बढ़कर लगभग 93,00,000 हैक्टेर (2010) तक पहुंच गया था। पराजीनी कपास को आमतौर पर बी. टी. कॉटन नाम से जाना जाता है।

कीटरोधिता: कीटरोधिता वह गुण है जिसमें एक ही पादप प्रजाति के कुछ विभेदो में अन्य विभेदों की तुलना में कीटों द्वारा अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है। कीटरोधी पौधों के उत्पादन के लिये मुख्य रूप से निम्नलिखित पराजीनों का स्थानान्तर किया जाता है।

बेसिलस थुरिजेनेसिस का क्राई जीन, लोबिया का ट्रिप्सिन निरोधी जीन 3, सीरीन-प्रोटिएज निरोधी जीन, लेक्टिन उपरोक्त जीनों में कोई जीन का उपयोग ज्यादा किया गया है। क्राई जीन या बी.टी. टाक्सिन जीन का स्रोत बेसिलस थुरिजेनेसिस नामक जीवाणु है अब तक इस प्रोटीन के लगभग 16 विकल्पी ज्ञात किये जा चुके है और प्रत्येक विकल्पी एक भिन्न कीटनाषी गुणधर्म वाला प्रोटीन उत्पन्न करता है जिससे इस क्रिया के फलस्वरूप कीटों की मृत्यु हो जाती है।

विषाणु रोधिता: जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से पौधों में पराजीन के द्वारा विषाणु रोधी पौधे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। उपरोक्त सफलता तम्बाकू, आलू, टमाटर, सोयाबीन, धान, नीबूं, एवं संतरा, मक्का आदि फसलों में प्राप्त हुई है। पौधों में पराजीन के उपयोग से विषाणुरोधिता उत्पन्न करने के लिये निम्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है-

आवरण प्रोटीन जीन द्वारा
संकरण सुरक्षा द्वारा
त्रुटिपूर्ण विषाणु जीनोम द्वारा
ऐंटीसेंस आर. एन.ए. द्वारा सुरक्षा

व्याधिरोधिता: इसकी निम्नलिखित प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।

पी. आर. प्रोटीन द्वारा: पी आर प्रोटीन सामान्यतः बीमारी से ग्रसित ऊतक में इकट्ठा हो जाती है। ये प्रोटीन कम अणुभार वाली होती है। इन प्रोटीन को 5 भागों में बाटा गया है जैसे तम्बाकू, फंगल पैथोजन की कोशिका भित्ति में उपस्थित काइटिन एवं ग्लूकेन का हाइड्रोलाइटिक एन्जाइमो द्वारा टूटना बीमारी रोधिता का आधार माना गया है। इस कार्य हेतु पौधों के बहुत सारे काइटिनेज जीन को निकाला एवं अध्ययन किया गया है। इस विधि द्वारा तम्बाकू, टमाटर, धान, सरसों, गाजर एवं आलू में जीवाणु एवं कवक के विरूद्ध बीमारी रोधिता प्राप्त करने में सफलता मिली है।

फाइटो एलोक्सिन द्वारा: ये कम अणुभार वाले सेकेण्डरी मेटावोलाइट्स है, जो पौधो में इनफेक्सन के फलस्वरूप बनते है। ये पदार्थ व्याधि रोधिता उत्पन्न करने में सहायक है।

जीन स्थान्तरण प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग हेतु जो बाहरी जीन स्थान्तरित किये जाते है, उन्हें पराजीन कहते है तथा इस प्रकार जो पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें पराजीनी पौधे कहते हैं।

निम्नलिखित विधियां में से किसी एक विधि द्वारा पौधों में समावेषित करा दिया जाता है।

ऐग्रोबैक्टीरियम द्वारा
इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा
जीनगन द्वारा
माइक्रोइंजेक्शन द्वारा
मेक्ररोइंजेक्शन द्वारा
सिलीकान कार्बाइड रेशे द्वारा
लिपोफेक्शन द्वारा जीन स्थान्तरण में आने वाली समस्यायें-

उपसंहार: हरित क्रांति का बडा उद्देश्य कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना था। हरित क्रांति द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की कृषि के क्षेत्र में पूरे विश्व विशेषकर ऐशिया महाद्वीप में भूख एवं गरीबी से लड़ने में समाज एवं सरकार को सहायता प्रदान की है। लेकिन आज जहां जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर कृषि योग्य भूमि में लगातार कमी आ रही है। अतः आज जो उत्पादन हमें मिल रहा है, यदि उसमें कीट एवं रोगों द्वारा होने वाले नुकसान को कम कर दिया जाये, तो यह दूसरे रूप में हमारे उत्पादन में वृद्धि को ही प्रदर्शित करेगा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न किये गये पराजीनी पौधों में रोग एवं कीट नियंत्रण के लिये सामान्यतः अलग से किसी रसायन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे किसानों पर आर्थिक दबाव कम हो जाता है और पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आती है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गयी पराजीनी फसलों का आज पूरे विश्व में लगभग 45 देशों में परीक्षण चल रहा है। आज कीट एवं रोगों के रोकथाम के बदलते हुये तरीके तथा ट्रांसजेनिक (पराजीनी) फसलों के महत्व व उपयोग को देखते हुये भारत सरकार ने इसके विकास पर ध्यान दिया है। विभिन्न अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा आलू, कपास, फूलगोभी, तम्बाकू, धान, सरसों, बैंगन, पत्ता गोभी, मिर्च इत्यादि फसलों की कीट एवं रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली प्रजातियां का विकास विभिन्न चरणों में है।

चना की बीमारियां ओर रोकथाम

अनिता चौधरी और जगजीवन राम
सैम हिग्गिन्बोटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंस इलाहाबाद

भारत की अनाज वाली फसलों में चने का क्षेत्रफल तथा पैदावार के हिसाब से क्रमशः पाँचवां व चौथा स्थान है। चना अच्छे जल निकास वाली दोमट रेतीली तथा हल्की मिट्टी में अच्छा होता है। खारी व कल्लर वाली मिट्टी इसके लिए अच्छी नहीं होती। इसे ऐसी मिट्टी में नहीं बोना चाहिए जिनका पी.एच.मूल्य 8.5 व विद्युत चालकता 0.8 डैसीसाइमन/मीटर से अधिक हो। सेमवाली जमीन भी इसके लिए ठीक नहीं, यहां तक कि जहां पानी की सतह ऊपर हो, वह मिट्टी भी इसके लिए ठीक नहीं रहती।

बीमारियों की रोकथाम

उखेड़ा: यह बीमारी बिजाई के 3-6 सप्ताह बाद दिखाई पड़ती है। पत्तियां मुरझा कर लुढ़क जाती हैं परन्तु उनमें हरापन बना रहता है। तने को चाकू से लम्बाई में काटने पर अन्दर से रसवाहिकी भूरी काली तथा भद्दी सी दिखाई पड़ती है। हालांकि इनमें से बहुत से लक्षण लवणता, भूमि में कम नमी तथा दीमक आदि द्वारा भी हो सकते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि इसके उपचार से पूर्व इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। उखेड़ा रोग से बचाव के लिए भूमि में नमी बनाए रखें तथा 10 अक्तूबर से पहले बिजाई न करें। बाविस्टीन 2.5 ग्राम/कि.ग्रा. बीज की दर से बीज को उपचारित करें। बिजाई से पूर्व बीज का उपचार जैविक फफूंदीनाशक ट्राईकोडरमा विरिडी (बायोडरमा) 4 ग्राम प्रति किलो ग्राम बीज विटावैक्स 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें।

जड़ गलन रोग: चने में फूल व फलियां बनते समय यह एक प्रमुख बीमारी है। इनका प्रकोप फसल की अंकुरण अवस्था में या फिर सिंचित क्षेत्रों में जब फसल बड़ी हो जाती है तब होता है। भूमि की सतह के पास पौधे के तने पर गहरे भूरे धब्बे दिखाई पड़ते हैं। रोगी पौधे के तने व पत्ते हल्के पीले रंग के होते हैं। मुख्य जड़ से नीचे का भाग गल जाने के कारण जमीन में ही रह जाता है। विषाणु रोग रोगी पौधे बौने रह जाते हैं तथा सन्तरी या भूरे रंग के हो जाते हैं। यह रोग काबली चने की अपेक्षा देसी चने में अधिक लगता है। जोड़ वाले स्थान पर थोड़ा चाकू से तिरछा काटने पर अन्दर से भूरा-सा दिखाई देता है। भूमि की नमी का ठीक ढंग से संरक्षण तथा 10 अक्तूबर के बाद चने की बिजाई करने से इस रोग से बचाव हो जाता है।

फफूद अंगमारियां: अधिक वर्षा यानि नमी व 18-20 डिग्री सैंटी ग्रेड तापमान अर्थात् ठण्डक रहने की अवस्था में ये रोग इस क्षेत्र में आ सकते हैं।

झुलसा रोग: इस बीमारी के आरम्भ में हल्के भूरे रंग के धब्बे पत्तों, तनों व फलियों पर दिखाई देते हैं। हरी फलियों पर ये काले धब्बे छोटी-छोटी गोलाकार आकृतियों में बदल जाते हैं। इनकी परिधि में हरे-भूरे रंग के दायरे दिखाई देने लगते हैं। तने और पत्तों के डंठल पर भूरे लम्बे-लम्बे धब्बे (3-4 सैं.मी.) बन जाते हैं व जिन पर फफूंद की बीजाणु-धारियां चूड़ीदार रेखाओं में काले बिन्दु के समान दिखाई देती है। रोगग्रस्त भाग जकड़ जाता है। बीमारी फैलने पर खेत का कुछ हिस्सा या सम्पूर्ण खेत ही रोग ग्रस्त हो जाता है।

आल्टरनेरिया अंगमारी: पत्तों पर बहुत छोटे, गोल भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। बीमारी की वृद्धि के साथ ये धब्बे भी हल्का पीला रंग धारण कर लेते हैं। परिणामस्वरूप पौधे गिरकर सूख जाते हैं। तने के परिगलित स्थान पर बीजाणु की रचना होती है। जड़ों पर इसके आक्रमण से पौधा कमजोर हो जाता है और फलियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है।

बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय अपनायें:

- जिस खेत में अंगमारी का आक्रमण रहा हो उसमें चने की फसल कदापि न लें।
- रोगमुक्त एवं स्वस्थ बीज ही बोयें। बीजगत संक्रमण से बचाव हेतु बाविस्टिन से बीजोपचार (2.5 ग्राम/किलोग्राम बीज) करें। यह उपचार रोग ग्राही किस्मों के लिए अत्यन्त आवश्यक है।
- रोगग्रस्त पौधों तथा उनके अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें।

चने का उपज बढ़ाने सम्बन्धी संकेतत:

- उन्नत किस्मों का प्रयोग करें।
- दीमक की रोकथाम के लिए बीज का उपचार अवश्य करें।
- चने का टीका लगाकर बिजाई सही ढंग व समय से करें।
- सिफारिश की गई खादों तथा राइजोबियम टीके का प्रयोग अवश्य करें
- जरूरत से ज्यादा (भारी) सिंचाई न करें।
- खरपतवारों की सही समय पर रोकथाम करें
- बारानी क्षेत्रों में चने में फूल आने के समय 2 प्रतिशत यूरिया का स्प्रे करें।

आदर्श मंडी कानून : निजी हाथ बदलेंगे मंडी-हाट

नई दिल्ली (विसं)। केंद्र सरकार कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) कानून में भारी बदलाव की तैयारी में है। नए आदर्श मंडी कानून में अधिसूचित बाजार क्षेत्र की अवधारणा को समाप्त करने और निजी मंडियों, किसान-उपभोक्ता बाजारों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना को बढ़ावा देने का प्रावधान है। साथ ही वेयरहाउसों को छोटी मंडियों में बदला जाएगा ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं और दाम मिल सके। सरकार वर्ष 2003 के पुराने आदर्श कानून की जगह नया आदर्श मंडी कानून ला रही है जिसमें ये प्रावधान किए गए हैं। इसमें सभी व्यापारियों को राज्य के भीतर सभी तक के कृषि बाजारों में कारोबार करने के लिए एकल लाइसेंस देने की वकालत की गई है। यानी व्यापारी कुछ फीस देकर मंडियों, छोटी मंडियों, निजी मंडियों और ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर कारोबार कर सकते हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सामान्य सजा का प्रावधान है। इसे छह महीने की सजा या जुर्माना या फिर दोनों में बदला जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक नैशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) जैसे ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए एकल राष्ट्रव्यापी लाइसेंस का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक सभी मौजूदा कारोबारी लाइसेंसों को कानून लागू होने के छह महीने के भीतर अंतरराज्यीय या राज्य के भीतर कारोबार के लिए एकल लाइसेंस में बदला जाएगा। कृषि विपणन राज्य का विषय है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि नए आदर्श कानून पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। आईआईएम-अहमदाबाद में कृषि प्रबंधन केंद्र के अध्यक्ष सुखपाल सिंह ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए विकल्पों की जरूरत है और मंडियां अब प्रभावी नहीं हैं। लेकिन कृषि विपणन राज्य का विषय है और यह देखना है कि सुधारों में से राज्य कितना अपनाते हैं। नए आदर्श कानून के मुताबिक सभी अधिसूचित कृषि जिंसों को मंडियों में और बाहर बेचा जा सकता है। साथ ही कृषि उपज प्रसंस्करण कंपनी, वालमार्ट और बिग बाजार जैसी खुदरा श्रृंखलाएं, इनसे जुड़े किसान सहकारी संघ और किसान-उत्पादक कंपनियां सीधे किसानों और उत्पादकों से कृषि उत्पाद खरीद सकती हैं। वे एक लाइसेंस लेकर किसी मंडी या निजी बाजार की सीमा के बाहर ऐसा कर सकती हैं। खरीदार यानी बड़ी खुदरा श्रृंखलाएं या प्रसंस्करण कंपनी संग्रह या एकत्रीकरण केंद्र खोल सकती हैं लेकिन उन्हें सरकार को अपनी मासिक रिपोर्ट, खाता और दूसरी जानकारी देनी होगी। बड़ी मात्रा में खरीद करने वाली कंपनियों पर आवश्यक वस्तु कानून के तहत भंडारण सीमा का नियम लागू नहीं होगा और उन्हें लाइसेंस फीस की 0.5 फीसदी राशि मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड में देनी होगी। इस आदर्श कानून को राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कृषि उपज विपणन (विकास एवं नियमन) कानून 2016 के नाम से जाना जाएगा। इसे सभी पक्षों के सुझाव के लिए सार्वजनिक किया गया है और इसके बारे में 15 मार्च तक सुझाव दिए जा सकते हैं। यह कृषि बाजारों और व्यापार को स्थिर करने के लिए केंद्र की त्रिस्तरीय कानूनी रणनीति की हिस्सा है।

मक्के की फसलों का दुश्मन है 'फॉल आर्मीवॉर्म'

लखनऊ (विसं)। घाना और साउथ अफ्रीका में पिछले साल मक्के की खेती में तबाही मचाने के बाद फॉल आर्मीवॉर्म (कीड़ा) अब एशिया की तरफ रुख कर रहा है। ब्रिटेन स्थित सेंटर फार एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंस के अनुसार अमेरिका से आए इस कीट ने घाना की फसलों को संक्रमित किया है। साउथ अफ्रीका में भी इसके होने की पुष्टि हो गई है। नेशनल पोस्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका में ये कीट वहां की प्रमुख फसल मक्का तक जांबिया से चलकर जिम्बाब्वे के रास्ते पहुंचा है। अमेरिका एग्रीकल्चर संस्थान के अनुसार कीट मालवी, मोजांबिक और नामीबिया जैसे देशों में पहुंच गया है। सेंटर फार एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंस के एक मेल ये खुलासा हुआ है कि कुछ सालों में पूरे अफ्रीका के खेत इस कीट के चपेट में होंगे। मेल मे बताया गया है कि फॉल आर्मीवॉर्म एशिया और भूमध्यसागरीय देशों में आने वाले समय में पहुंच जाएगा और ये दुनिया की खेती का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ये कीड़ा खेतों में फैल जाता है और फसलों की पत्तियां और तने को खा जाता है, ये अफ्रीकन देशों में पाए जाने वाले परंपरागत कीड़ों से ज्यादा खतरनाक है। एक शोध पत्रिका के मुताबिक फसलों के लिए ये प्रजाति बहुत ही खतरनाक है। ये कीड़ा मक्के की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। घाना में ज्यादतर किसान मक्के की खेती करते हैं। घाना में इस समय 35 सालों में सूखे की स्थिति सबसे भयावह है, ऐसे में हालात और खराब हो सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कीड़ा अच्छी फसलों के लिए प्रयास कर रहे किसानों का उत्साह गिराने वाला है। कीड़े की वजह से फसलों की पैदावार लगभग 73 प्रतिशत तक गिरी है।

दलहन उत्पादन में इजाफे के लिए पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार

नई दिल्ली (विसं)। केंद्र सरकार ने 2020-21 तक दलहन के सालाना उत्पादन में 2.4 करोड़ टन से ज्यादा के इजाफे के लिए एक पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की है। योजना से देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। योजना के पहले साल यानी 2016-17 में दलहन का उत्पादन रिकॉर्ड 2.2 करोड़ टन से ज्यादा होने का अनुमान है जो लक्ष्य से नौ लाख टन अधिक है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों आदि के परामर्श से तैयार की गई है। वर्षा सिंचित और अधिक क्षेत्रों को खेती के तहत लाने के लिए कई राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी भारत में अनाज, तिलहन और व्यावसायिक फसलों के साथ अंतर-कृषि अपनाकर उपज बढ़ाई जा रही है। केंद्र अरहर की खेती को भी प्रोत्साहित कर रहा है और उसने इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया है। किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने 20 टन से कुछ ज्यादा की मात्रा बफर स्टॉक के लिए खरीदने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कुल आवंटन का लगभग 60 प्रतिशत दलहन के लिए है। उधर, सरकार ने कहा है कि 2016-17 (जुलाई-जून) में खाद्यान्न वृद्धि ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह 2015-16 से 8.1 प्रतिशत ज्यादा यानी 27.198 करोड़ टन है।

आलू का घाटा पूरा करेगी मक्के की खेती

लखनऊ (विसं)। धान के बाद आलू किसानों को कीमतों ने झटका दिया है। थोक में 2-3 रुपए किलो में बिक रहे आलू से किसानों की लागत नहीं निकल पाई है। इस घाटे से उबरने के लिए किसान बड़े पैमाने पर मक्का बो रहे हैं। बाराबंकी से लेकर फरुर्खाबाद तक में मक्के का रकबा बढ़ा है। लखनऊ से दिल्ली की आजादपुर मंडी तक आलू 200-500 रुपये कुंटल बिक रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के किसान परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में आलू के गढ़ फरुर्खाबाद, हाथरस, अलीगढ़, कन्नौज, एटा, कासगंज में किसान अब मक्का बो रहे हैं। आलू के बाद दूसरी फसल किसानों के लिए हमेशा कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली रही है। आलू में डाली गई खादें, दूसरी फसलों में भी काम आती हैं। बाराबंकी-सीतापुर और गोंडा समेत कई जिलों में किसान आलू के बाद मेंथा लगाते रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में मक्के का रकबा तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2016-17 के अनुसार जायद की फसल में एक लाख 15 हजार हेक्टेयर, खरीफ की फसल में 7.38 लाख हेक्टेयर मक्के की बुवाई हुई थी। सुबह के नाश्ते में कॉनफ्लेक्स से लेकर फिल्म देखने के दौरान पॉपकार्न और सड़कों के किनारे बिकने वाली छल्ली तक मक्के का उपयोग बढ़ा है। पिछले कई वर्षों से मक्का की खेती करने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसान एक बीघे में 15-20 कुंतल मक्का का उत्पादन ले रहे हैं। मक्का की खेती पर किसानों को बीज में 100 रुपए सब्सिडी मिलती है और साल में तीन बार मक्का की खेती होती है। किसान सीजन के हिसाब से मक्का के बीज का चयन करें।

बरसों का रिकॉर्ड तोड़ेगा गेहूं का उत्पादन

राजगढ़ (विसं)। मौसम और बारिश की मेहरबानी ने इस बार अन्नदाता को जो उत्पादन दिया है, वह अपने खुद के ही पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगा। पिछले चार बरसों में कभी भी प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन का आंकड़ा 39 क्विंटल को नहीं छू पाया है जबकि इस बार यह आंकड़ा 42 से 44 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जाने का ठोस अनुमान लगाया जा रहा है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा रहा कि कुछ भी हो जाए अब 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन तो होगा ही। बहरहाल, यदि ऐसा हुआ तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटेगा और किसानों की वजह से एक बार फिर बाजार गुलजार हो जाएगा। उधर, कृषि उपज मंडी में नए गेहूं की बंपर आवक ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं। कृषि विभाग के मुताबिक इस बार क्षेत्र में कुल 65 हजार हेक्टेयर में गेहूं बोए गए थे। कृषि विभाग के मुताबिक यह आंकड़ा भी पिछले कई बरसों की तुलना में ज्यादा ही रहा था। खैर, इस 65 हजार हेक्टेयर में प्रति हेक्टेयर उत्पादन का अनुमान 42 से 44 क्विंटल लगाया जा रहा है। इस लिहाज से यदि देखा जाए तो 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से भी गेहूं का उत्पादन करीब 27 लाख 30 हजार क्विंटल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि विभाग के मुताबिक वर्ष 2012-13 में क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन 34.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया था। वहीं वर्ष 2013-14 में इसमें कमी आई थी और यह आंकड़ा महज 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर सिमटकर रह गया था। इसके बाद इसमें बढ़ोत्तरी हुई और यह आंकड़ा 2014-15 में 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तो वर्ष 2015-16 में 38.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंचा। इस वर्ष यानी 2016-17 में गेहूं का उत्पादन 42 से 44 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह आंकड़ा किसी भी हाल में 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से नीचे नहीं आएगा, यह भी दावा किया जा रहा है।

नए गेहूं का श्रीगणेश, भाव 1700 से ज्यादा: नए गेहूं का श्रीगणेश हो चुका है और मंडी नए गेहूं की सुगंध से महकने लगी है। मंडी में गेहूं बिकने के लिए पहुंचा तो भाव 1750 से 1911 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आने वाले समय में मंडी में बहुत अधिक मात्रा में गेहूं पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि उपज मंडी के प्रभारी अधीक्षक हरिशंकर जोशी के मुताबिक मंडी में 1941 क्विंटल सोयाबीन आया। इसके भाव 2750 से 3141 रुपए प्रति क्विंटल रहे। सोयाबीन के भावों में करीब 100 रु. की गिरावट दर्ज की गई है।

कृषि उपज मंडी में तौल कांटे की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा

धार (विसं)। भारतीय किसान संघ ने धार कृषि उपज मंडी में तौल कांटे की समस्या को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। आगामी रबी सीजन में गेहूं की बंपर पैदावार होना है। इस लिहाज से किसानों ने अभी से चिंता जाहिर की है। मंडी में तीन तौल कांटे हैं और उसमें से एक ही चालू है। ऐसे में जबकि किसानों को नोटबंदी के बाद किसानों को परेशानी हो रही है तो उन्होंने मंडी में चेक से भुगतान की बजाय पूर्ण रूप से आरटीजीएस से भुगतान करने की मांग की है। इसके अलावा 25 हजार रुपए उपज बेचने के बाद नकद दिए जाए ताकि किसान अपनी जरूरत की सामग्री तुरंत खरीद सके। रबी सीजन के तहत गेहूं और चने की आवक होना है। धार कृषि उपज मंडी ए ग्रेड की मंडी है। यहां पर कुछ दिन पहले तौल को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। ऐसे में जबकि मंडी में तीन तौल कांटे स्थापित हैं।

भारतीय खाद्य निगम को भंडारण का गम!

मुंबई (कासं)। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को पिछले दो वर्षों में अनाज के भंडारण की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था लेकिन इस बार गेहूं का ज्यादा उत्पादन होने और उसकी सरकारी खरीद बढ़ने पर निगम के सामने अनाज के भंडारण का गंभीर मसला खड़ा हो सकता है। संभावित स्थिति से निपटने के लिए निगम अभी से रणनीति बनाने में जुट गया है। केंद्रीय खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले गेहूं खरीद सत्र में सरकार ने 3.3 करोड़ टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। यह वर्ष 2016 में की गई 2.29 करोड़ टन खरीद से करीब 33 फीसदी अधिक है। हालांकि गेहूं खरीद का यह लक्ष्य पूरे साल के लिए रखा गया है लेकिन इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा अप्रैल-जून की तिमाही के दौरान ही खरीद लिया जाएगा। इसी तरह खरीफ फसलों के विपणन वर्ष 2016-17 में सरकारी एजेंसियों ने आंकड़ों के मुताबिक 4.95 करोड़ टन धान की खरीद कर ली है। इसके अलावा एफसीआई ने छोटे किसानों के कंसोर्टियम एसएफएसी और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) के साथ मिलकर 15 फरवरी तक करीब 10 लाख टन दालें भी खरीदी हैं। सरकार ने पहले खरीफ सत्र में उपजे धान के लिए 3.3 करोड़ टन खरीद का लक्ष्य रखा था लेकिन बाद में उसमें 50 लाख टन की बढ़ोतरी कर दी गई। एफसीआई सूत्रों ने बताया कि सरकार ने उसे देश के अलग-अलग इलाकों से दालों की खरीद करने को कहा है लेकिन उसे रखने के लिए अतिरिक्त स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी करीब 1 करोड़ टन बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में हमें इस साल खरीदे हुए अनाज को रखने के लिए अतिरिक्त स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम निजी गोदामों की सेवाएं ले सकते हैं। पिछले दो वर्षों में तो अनाज उत्पादन कम रहने से सरकारी खरीद में भी उछाल नहीं आई थी। इस वजह से एफसीआई को भंडारण के लिए जगह की कमी महसूस नहीं हुई थी। उस दौरान निजी गोदामों की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे इस साल भी निजी गोदामों की जरूरत तभी पड़ेगी जब बड़ी बहुराष्ट्रीय अनाज कंपनियों की तरफ से किसानों को दी जाने वाली कीमतें सरकारी मूल्य से कम होंगी। अगर कंपनियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक भाव दिया तो भरोसेमंद कंपनियां अधिक अनाज खरीद सकती हैं। इसके बावजूद एफसीआई ने मार्च के अंत से शुरू होने वाली खरीद प्रक्रिया में 2.55 करोड़ टन से लेकर 2.85 करोड़ टन गेहूं खरीदने की योजना बनाई है।

कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

धार (विसं)। कृषि विज्ञान केंद्र धार में सोमवार को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कृषि विश्वविद्यालय के प्रमंड सदस्य राम पाटीदार ने किसानों के समक्ष अपने अनुभव बांटे एवं उन्होंने देश व जिले में व्याप्त अनेक अद्वितीय प्रजातियों की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को इनके प्रति जागरूक रहना चाहिए अन्यथा इन प्रजातियों को कोई अन्य व्यक्ति, समूह या कंपनी अपने नाम से पंजीयन कराकर लाभ ले सकते हैं। कृषि महविद्यालय इंदौर प्राध्यापक डॉ. जगदीश सिंह अध्यक्षता की। कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि महविद्यालय इंदौर डॉ. इंदू स्वरूप, प्रमंडल सदस्य श्रीराम पाटीदार, उपसंचालक उद्यानिकी आशीष कनेश, सूर्यकांत बरोदिया, सेडमेप के प्रकाश तिलक व कृषक अमृतलाल पाटीदार आदि उपस्थित थे।

नई कृषि जिंस में वायदा को जल्द मंजूरी

मुंबई (कासं)। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) जल्द ही डिगम सोया तेल में वायदा कारोबार को मंजूरी देने जा रहा है। जिंस एक्सचेंजों, मुख्य रूप से नैशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) ने डिगम सोया तेल में वायदा कारोबार शुरू करने की मंजूरी हासिल करने के लिए सेबी में आवेदन किया था। एक्सचेंज के सूत्रों के मुताबिक एनसीडीईएक्स ने पीली मटर, कालीमिर्च और सरसों खली में वायदा कारोबार की मंजूरी के लिए भी सेबी में आवेदन किया था। यह एक्सचेंज फिर से चना वायदा शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसे ऊंची कीमतों की वजह से पिछले साल रोक दिया गया था। हालांकि अब चने की कीमतें सामान्य स्तर पर हैं। यहां तक कि एमसीएक्स भी अपने कृषि जिंस खंड के विस्तार का इंतजार कर रहा है। एक्सचेंज ने कुछ अन्य कृषि जिंसों में वायदा कारोबार का प्रस्ताव रखा है और अब वह सेबी की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। सेबी के सूत्रों ने कहा, हम एनसीडीईएक्स और एमसीएक्स समेत सभी जिंस एक्सचेंजों को डिगम सोया तेल में वायदा कारोबार शुरू करने की जल्द ही मंजूरी देंगे। हालांकि सूत्र ने मंजूरी का निश्चित समय नहीं बताया, लेकिन कहा कि मंजूरी अंतिम चरण में है। सूत्रों ने कहा, अब यह जिम्मा एक्सचेंजों पर है कि वे अनुबंध विकसित करें और भागीदार जुटाएं। हम सभी एक्सचेंजों को वायदा कारोबार की मंजूरी देंगे। डिगम सोया तेल देश में आयातित अप्रसंस्कृत तेल है। इसका आयात मुख्य रूप से अर्जेन्टीना और ब्राजील से होता है, ताकि देश में खाद्य तेल की कमी की भरपाई की जा सके। तेल क्षेत्र की शीर्ष संस्था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2015 से अक्टूबर 2016 के बीच देश में डिगम सोया तेल का कुल आयात 42 लाख टन रहा। डिगम सोया तेल की आयातित मात्रा देश के सभी जिंस वायदा एक्सचेंजों के गोदाम सेवा प्रदाताओं (डब्ल्यूएसपी) द्वारा प्रबंधित कुल कृषि जिंसों से करीब 50 फीसदी अधिक है। देश के सभी वायदा एक्सचेंजों के सभी गोदाम सेवा प्रदाता करीब 30 लाख टन कृषि जिंसों का प्रबंधन करते हैं। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस समय भारतीय कारोबारी वायदा एक्सचेंजों पर किसी कीमत जोखिम की हेजिंग किए बिना डिगम सोया तेल का आयात करते हैं। उन्होंने कहा, डिगम तेल में वायदा को मंजूरी मिलने से भारतीय कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि वे डेरिवेटिव प्लेटफॉर्मों पर कीमत जोखिम की हेजिंग कर अपना नुकसान कम करने में सक्षम होंगे। इस समय देश के एक्सचेंज सोयाबीन, रिफाइंड सोया तेल और खली में वायदा कारोबार की सुविधा देते हैं। डिगम सोया तेल में वायदा कारोबार की मंजूरी से घरेलू एक्सचेंजों पर सोया खंड हेजिंग और कीमत निर्धारण के लिहाज से संपूर्ण हो जाएगा।

एक पौधे में फलेगा 25 किलो टमाटर!

नई दिल्ली (विसं)। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के मद्देनजर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वैज्ञानिक टमाटर की एक ऐसी किस्म विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी किसान प्रति पौधा 20 से 25 किलोग्राम टमाटर की पैदावार कर अपनी आय में भारी वृद्धि कर सकें। परिषद के कर्नाटक स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर) हेसरघट्टा, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में आ रहे उतार-चढ़ाव, अधिक वर्षा और सूखे की समस्या तथा बीमारियों के बढ़ते प्रकोपों को देखते हुए टमाटर की तीन-चार उच्च उत्पादकता वाले संकर किस्मों के विकास का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है जिसे किसानों को खेती के लिए किसी भी समय जारी किया जा सकता है।

संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक टी एच सिंह ने हाल में दिल्ली से गए संवाददाताओं को बताया कि तीन-चार साल पहले आईआईएचआर ने प्रति पौधा 19 किलो पैदावार देने वाले टमाटर की अर्क रक्षक किस्म को खेती के लिए जारी किया था। कर्नाटक के कई प्रगतिशील किसान अपने खेतों में अर्क रक्षक से प्रति पौधा 19 किलो पैदावार ले रहे हैं जिनमें चन्द्रप्पा प्रमुख हैं। टमाटर की अन्य किस्मों की पैदावार प्रति एकड़ 50 टन तक ली जाती है जबकि अर्क रक्षक की पैदावार आदर्श स्थिति में 78 टन तक ली गई है।

डा. सिंह ने बताया कि अर्क रक्षक मध्यम आकार का है और इसके एक फल का वजन 80 से 100 ग्राम के बीच होता है। वैज्ञानिक जिस नई किस्म का विकास कर रहे हैं उसका वजन 120 ग्राम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही ऊष्मा प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो टमाटर की किस्में हैं वो 30 से 35 डिग्री तापमान को सहन कर सकते हैं और अच्छी पैदावार देते हैं लेकिन नई किस्म 40 डिग्री तापमान में भी बेहतर पैदावार देंगे। नई किस्म को वायरस के कारण होने वाली बीमारी 'टाम्यों' प्रतिरोधी भी बनाया जा रहा है।

अरंडी में 25 फीसदी कमी के आसार

अहमदाबाद (विसं)। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सी) ने 2016-17 के दौरान अरंडी उत्पादन में 25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 10.6 लाख टन रहने का अनुमान जताया है जबकि 2015-16 के दौरान यह 14.3 लाख टन था।

अरंडी उपजाने वाले राज्यों में इस जिंस के अनुमान का अध्ययन करने के लिए एसोसिएशन ने नीलसन इंडिया को अधिकृत किया था।

आलू किसानों की मुश्किलें कम करने के लिए घटाए शुल्क

जालंधर (विसं)। पंजाब में आलू की कम कीमतों को देखते हुए राज्य सरकार ने पंजाब एग्रो और मार्क फेड को 'न नफा न नुकसान' आधार पर प्रभावी तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। कीमतें कम रहने से आलू किसानों को मुश्किलों से निकालने के लिए राज्य सरकार ने यह आदेश दिया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आलू पर बाजार शुल्क और ग्रामीण विकास शुल्क दोनों 2 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कमीशन एजेंट का शुल्क भी कम करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से यह शुल्क 5 प्रतिशत से कम कर 1 प्रतिशत कर दिया है। बादल ने पंजाब एग्रो और मार्कफेड को रूस, दुबई, ईरान, श्रीलंका सहित दूसरे देशों को आलू निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए। आलू के निर्यात पर राज्य सरकार क्षति-पूर्ति करेगी। कृषि विभाग देश में ही दूसरे राज्यों एवं बाजारों में आलू की खेप भेजने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

चीनी मिलों पर किसानों के 5,795 करोड़ बकाया

नई दिल्ली (विसं)। इस बार अच्छी कीमत के बावजूद उत्तर प्रदेश में फरवरी के दूसरे सप्ताह तक चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का 5,795 करोड़ रुपये बकाया था।

यानी उद्योग के लिए अच्छा साल होने पर भी किसानों को अच्छा फल नहीं मिल पाया है। चालू चीनी सीजन 1 अक्टूबर से (यह सितंबर के आखिर तक चलता है) शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की देनदारी के 5,795 करोड़ रुपये में से कंपनियों का हिस्सा 92 प्रतिशत के साथ 5,320 करोड़ रुपये था। इस कुल बकाया में से 55 प्रतिशत केवल चार कंपनियों पर ही बाकी था। गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर उनका भुगतान मिलना चाहिए। इसके बाद यह राशि बकाया की श्रेणी में आ जाती है। इस सीजन में पिछले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में 16,894 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था जिसमें से 66 प्रतिशत यानी 11,098 करोड़ रुपये ही दिए गए। राज्य में 116 मिलें चल रही हैं। इनमें से 91 मिलें निजी क्षेत्र में और 24 सहकारी क्षेत्र में हैं। एक सरकारी चीनी मिल है। उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक में 910 करोड़ रुपये, गुजरात में 455 करोड़ रुपये, तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र में 363 करोड़ रुपये का बकाया है।

झींगा निर्यात पर लग सकता है आघात

भुवनेश्वर (विसं)। समुद्री खाद्य के निर्यात पर चोट करते हुए भारत के सबसे बड़े (मूल्य के लिहाज से) समुद्री उत्पादों के आयातकर्ता देश अमेरिका ने भारत से जाने वाली खेपों की जांच की कार्रवाई के दायरे में इजाफा कर दिया है। उद्योग के सूत्रों ने कहा कि अमेरिका द्वारा एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरिया की जांच के लिए 140 से ज्यादा खेपों को रोका गया है। इससे अमेरिकी निर्यात पर असर पड़ सकता है। एक निर्यातक ने कहा, जनवरी में एक महीने के दौरान इतनी खेप को रोका जाना अभूतपूर्व है। इसने निर्यातकों के बीच खलबली है।

किसानों को खेती-बाड़ी उपयोगी जानकारी देगा 'माई एग्री गुरू' ऐप

नई दिल्ली (विसं)। महिंद्रा एंड महिंद्रा की पूर्ण अनुषंगी महिंद्रा एग्री सोल्यूशंस लिमिटेड (एमएएसएल) ने किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हिंदी व अंग्रेजी में उपयोगी सूचना एवं सलाह सुलभ कराने के लिए मोबाइल ऐप 'माई एग्री गुरू' शुरू किया। इसे अन्य भारतीय भाषाओं में भी शुरू किया जाएगा। महिंद्रा एग्री सोल्यूशंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ अशोक शर्मा ने कहा, "हमने किसानों को फसलों, कीमत और खेती-बाड़ी से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए मोबाइल ऐप 'माई एग्री गुरू' शुरू किया है। यह एंड्रायड प्लेटफार्म पर पूरे देश में उपलब्ध है।" उन्होंने कहा कि फिलहाल यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी में है और जल्दी ही हम गुजराती, मराठी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इसे जारी करेंगे। इस ऐप के जरिए किसान विभिन्न फसलों की खेती-बाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बाजार कीमत, मौसम और विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों से बातचीत कर सकते हैं। शर्मा ने कहा, "महिंद्रा भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के साथ काम कर रही है ताकि पांच दिन की अवधि के लिये मौसम पूर्वानुमान प्राप्त कर सके और किसानों के साथ उसे साझा कर सके। साथ ही कंपनी ने वास्तविक समय के आधार देश के विभिन्न मंडियों में कीमत साझा करने के लिए जिंस बाजार एनसीडीईएक्स के साथ गठजोड़ किया है। इससे किसान कीमतों की तुलना कर सकेंगे और अपना माल वहां बेच पाएंगे जहां उन्हें अधिक लाभ हो।"

उन्होंने कहा, "यह ऐप सरकार के 'डिजिटल इंडिया' के तहत कृषि क्षेत्र को डिजिटल रूप देने की योजना को आगे बढ़ाएगा। साथ ही 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने मे भी मददगार होगा। यह ऐप किसानों को खेती-बाड़ी के हर चरण में सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करेगा। इससे कृषि उत्पादकता और कृषि आय दोनों में वृद्धि होगी।"

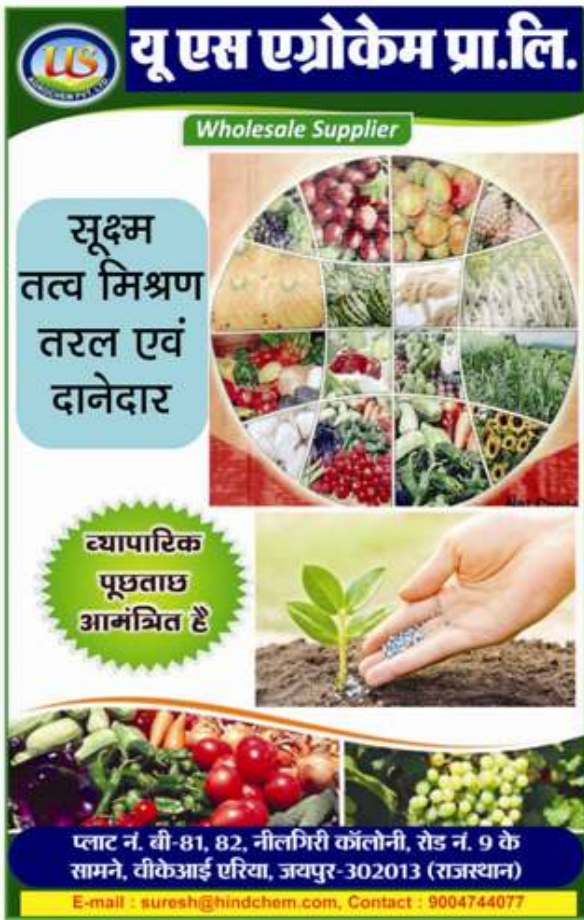

सागौन की उन्नत खेती कर उठाएं लाभ

सागौन को इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है जो वर्बेनेसी परिवार से संबंध रखता है। इसका वैज्ञानिक नाम टैक्टोना ग्रांडिस है। इसका पेड़ बहुत लंबा होता है और अच्छी किस्म की लकड़ी पैदा करता है। यही वजह है कि इसकी देश और विदेश के बाजार में अच्छी डिमांड है। सागौन से बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसलिए सागौन की लकड़ी से बने फर्नीचर की घर और ऑफिस दोनों जगहों पर भारी मांग हमेशा रहती है। पूरी दुनिया में सागौन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आम तौर पर सागौन की अच्छी किस्म की खेती की जाती है जिसमें कम रिस्क पर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लगभग 14 सालों में अच्छी सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी के साथ वैज्ञानिक प्रबंधन के जरिए एक पेड़ से 10 से 15 क्यूबिक फीट लकड़ी हासिल की जा सकती है। इस दौरान पेड़ के मुख्य तने की लंबाई 25-30 फीट, मोटाई 35-45 इंच तक हो जाती है। आमतौर पर एक एकड़ में 400 अच्छी क्वालिटी के आनुवांशिक पेड़ तैयार किये जा सकते हैं। इसके लिए सागौन के पौधों के बीच 9/12 फीट का अंतराल रखना होता है।

भारत में सागौन (Teakwood)के कई प्रकार हैं-

नीलांबर (मालाबार) सागौन
दक्षिणी और मध्य अमेरिकन सागौन
पश्चिमी अफ्रीकन सागौन
अदिलाबाद सागौन
गोदावरी सागौन
कोन्नी सागौन

सागौन की खेती के लिए उपयुक्त मौसम: सागौन के लिए नमी और उष्ण कटिबंधीय वातावरण जरूरी होता है। यह ज्यादा तापमान को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है लेकिन सागौन की बेहतर विकास के लिए उच्चतम 39 से 44 डिग्री सेंटीग्रेट और निम्नतम 13 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त है। 1200 से 2500 मिलीमीटर बारिश वाले इलाके में इसकी अच्छी पैदावार होती है। इसकी खेती के लिए बारिश, नमी, मिट्टी के साथ-साथ रोशनी और तापमान भी अहम भूमिका निभाता है।

सागौन खेती में मिट्टी की भूमिका: सागौन की सबसे अच्छी पैदावार जलोढ़ मिट्टी में होती है जिसमे चूना-पत्थर, शीष्ट, शैल, भूसी और कुछ ज्वालामुखीय चट्टानें जैसे कि बैसाल्ट मिली हो। वहीं, इसके विपरीत सूखी बलुवाई, छिछली, अम्लीय (6.0पीएच) और दलदलीय मिट्टी में पैदावार बुरी तरह प्रभावित होती है। सॉयल पीएच यानी मिट्टी में अम्लता की मात्रा ही खेती के क्षेत्र और विकास को निर्धारित करती है। सागौन के वन में सॉयल पीएच का रेंज व्यापक है, जो 5.0-8.0 के 6.5-7.5 बीच होता है।

सागौन खेती में कैल्सियम की भूमिका: कैल्सियम, फोस्फोरस, पोटैशियम, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक तत्वों से भरपूर मिट्टी सागौन के लिए बेहद मुफीद है। कई शोध परिणाम बताते हैं कि सागौन के विकास और लंबाई के लिए कैल्सियम की ज्यादा मात्रा बेहद जरूरी है। यही वजह है कि सागौन को कैलकेरियस प्रजाति का नाम दिया गया है। सागौन की खेती कहां होगी इसको निर्धारित करने में कैल्सियम की मात्रा अहम भूमिका निभाती है। साथ ही जहां सागौन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उससे ये भी साबित होता है कि वहां उतना ही ज्यादा कैल्सियम है। जंगली इलाकों में जहां नर्सरी स्थापित की जाती है वो बेहद ऊर्वरक होती है और उसमे अलग से खाद मिलाने की जरूरत नहीं होती है।

नर्सरी में सागौन पौधारोपन: सागौन की नर्सरी के लिए हल्की ढाल युक्त अच्छी सूखी हुई बलुई मिट्टी वाला क्षेत्र जरूरी होता है। नर्सरी की एक क्यारी 1.2 मीटर की होती है। इसमे 0.3 मी.से 0.6 मी की जगह छोड़ी जाती है। साथ ही क्यारियों की लाइन के लिए 0.6 से 1.6 मी. की जगह छोड़ी जाती है। एक क्यारी में 400-800 तक पौधे पैदा होते हैं। इसके लिए क्यारी की खुदाई होती है। इसे करीब 0.3 मी. तक खोदा जाता है और जड़, खूंटी और कंकड़ को निकाला जाता है। जमीन पर पड़े ढेले को अच्छी तरह तोड़ कर मिला दिया जाता है। इस मिट्टी को एक महीने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसे क्यारी में बालू और ऑर्गेनिक खाद के साथ भर दिया जाता है। नमी वाले इलाके में जल जमाव को रोकने के लिए जमीन के स्तर से क्यारी को 30 सेमी तक ऊंचा उठाया जाता है। सूखे इलाके में क्यारी को जमीन के स्तर पर रखा जाता है। खासकर बेहद सूखे इलाके में जहां 750 एमएम बारिश होती है वहां पानी में थोड़ी डूबी हुई क्यारियां अच्छा रिजल्ट देती है। एक मानक क्यारी से जो कि 12 मी. की होती है उसमे करीब 3 से 12 किलो बीज इस्तेमाल होता है। वहीं, केरल के निलांबुर में करीब 5 किलो बीज का इस्तेमाल होता है।

सागौन की रोपाई के तरीके: फैलाकर या छितराकर और क्रमिक या डिबलिंग तरीके से 5 से 10 फीसदी अलग रखकर बुआई की जाती है। क्रमिक या डिबलिंग तरीके से बुआई ज्यादा फायदेमंद होता है अच्छी और मजबूती से बढ़ने वाली होती है। आमतौर पर क्यारियों को उपरी शेड की जरूरत नहीं होती है। सिवा बहुत सूखे इलाके के जहां सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे हालात में यहां खर-पतवार भी नहीं पनप पाता है।

सागौन रोपन में जगह का महत्व-

सागौन का रोपन 2×2, 2.5 × 2.5 या 3×3 मी. के बीच होना चाहिये। इसे दूसरी फसलों के साथ भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 4×4 या 5×1 मी. का गैप या अंतराल रखना जरूरी है।

सागौन रोपन में जमीन की तैयारी और खेती एवं सावधानियां: सागौन के पौधारोपन के लिए जगह चौरस या फिर हल्की ढलान वाला हो (जिसमे अच्छे से पानी निकलने की व्यवस्था हो) । शैल और शीस्ट से युक्त मिट्टी सागौन के लिए अच्छा होता है। सागौन की अच्छी बढ़त के लिए जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं, लैटेराइट या उसकी बजरी, चिकनी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, बलुई और बजरी सागौन के पौधे के लिए अच्छा नहीं होता है। पौधारोपन के लिए पूरी जमीन की अच्छी जुताई, एक लेवल में करना जरूरी होता है। पौधारोपन की जगह पर सही दूरी पर एक सीध में गड्ढा खुदाई जरूरी होता है। सागौन रोपन के लिए कुछ जरूरी बातें-

पूर्व अंकुरित खूंटी या पॉली पॉट का इस्तेमाल करें

45सेमी. × 45 सेमी. × 45 सेमी. की नाप के गड्ढे की खुदाई करें। मिट्टी में मसाला, कृषि क्षेत्र की खाद और कीटनाशक को दोबारा डालें। साथ ही बजरी वाले इलाके के खोदे गए गड्ढे में ऑर्गेनिक खाद युक्त अच्छी मिट्टी डालें। पौधारोपन के दौरान गड्ढे में 100 ग्राम खाद मिलाएं और उसके बाद मिट्टी की ऊर्वरता को देखते हुए अलग-अलग मात्रा में खाद मिलाते रहें सागौन की खेती के लिए सबसे अच्छा मौसम मॉनसून का होता है, खासकर पहली बारिश का वक्त पौधे की अच्छी बढ़त के लिए बीच-बीच में मिट्टी की निराई-गुड़ाई का भी काम करते रहना चाहिए, पहले साल में एक बार, दूसरे साल में दो बार और तीसरे साल में एक बार पर्याप्त है। पौधारोपन के बाद मिट्टी की तैयारी को अंतिम रुप दें और जहां जरूरी है वहां सिंचाई की व्यवस्था करें। शुरुआती साल में खर-पतवार को हटाने का काम करना सागौन की अच्छी बढ़त को सुनिश्चित करता है।

खर-पतवार का नियंत्रण : सागौन के पौधारोपन के शुरुआती दो-तीन सालों में खर-पतवार नियंत्रण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नियमित अंतराल पर खतर-पतवार हटाने का अभियान चलाते रहना चाहिए। पहले साल में तीन बार, दूसरे साल में दो **(शेष पेज 7 पर)**

पेज 6 का शेष...

सागौन की उन्नत खेती...

बार और तीसरे साल में एक बार ये अभियान अच्छी तरह चलाना आवश्यक है। यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि सागौन ऐसी प्रजाति का पेड़ है जिसकी वृद्धि और विकास के लिये सूर्य की पर्याप्त रोशनी जरूरी है।

सागौन खेती में सिंचाई की तकनीक: शुरुआती दिनों में पौधे की वृद्धि के लिए सिंचाई बेहद अहम है। खरपतवार नियंत्रण के साथ-साथ सिंचाई भी चलती रहनी चाहिए जिसका अनुपात 3×2×1 है। इसके साथ ही मिट्टी का भी काम चलते रहना चाहिए। अगस्त और सितंबर महीने में दो बार खाद डालना चाहिए। लगातार तीन साल तक प्रत्येक पौधे में 50 ग्राम एनपीके (15:15:15) डाला जाना चाहिए। नियमित तौर पर सिंचाई और पौधे की छंटाई से तने की चौड़ाई बढ़ जाती है। ये सब कुछ पौधे के शीर्ष भाग के विकास पर निर्भर करता है जैसे कि प्रति एकड़ वृक्षों की संख्या में कमी। दूसरे शब्दों में अधिक ऊंचाई वाले पौधे लेकिन कम संख्या या फिर कम ऊंचाई वाले पौधे लेकिन संख्या ज्यादा। सिंचाई सुविधायुक्त सागौन के पेड़ तेजी से बढ़ते हैं लेकिन वहीं रसदार लकड़ी की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में पौधे का तना कमजोर हो जाता है और हवा से इसे नुकसान पहुंचता है। ऐसे में पौधे में पानी के फफोले बनने लग जाते हैं। ऐसे पेड़ बाहर से दिखने में मजबूत दिखते हैं लेकिन पानी के जमाव की वजह से पैदा हुए फंगस की वजह से अंदर से खोखला हो जाता है। सागौन की खेती में पौधे आमतौर पर 13 से 40 डिग्री तापमान के बीच अच्छी तरह से बढ़ते हैं। प्रत्येक साल 1250 से 3750 एमएम की बारिश इसकी खेती के लिए पर्याप्त है। वहीं, अच्छी गुणवत्ता वाले पेड़ के लिए साल में चार महीना सूखा मौसम चाहिए और इस दौरान 60 एमएम से कम बारिश ही अच्छी होती है। पेड़ के बीच अंतर, तने की काट-छांट की टाइमिंग से पौधे के विकास पर फर्क पड़ता है। कांट-छांट में अगर देरी की गई या फिर पहले या ज्यादा कांट-छांट की जाती है तो इससे भी इसकी खेती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सागौन की खेती में कटाई-छंटाई का महत्व: आमतौर पर सागौन के पौधे की कटाई-छटाई पौधा रोपन के पांच से दस साल के बीच की जाती है। इस दौरान जगह की गुणवत्ता और पौधों के बीच अंतराल को भी ध्यान में रखा जाता है। वहीं अच्छी जगह और नजदीकी अंतराल (1.8×1.8 मी. और 2×2) वाले पौधे की पहली और दूसरी कटाई-छंटाई का काम पाचवें और दसवें साल पर की जाती है। दूसरी बार कटाई-छंटाई के बाद 25 फीसदी पौधे को विकास के लिए छोड़ दिया जाता है।

सागौन पौधारोपन के बीच अंतर फसल: शुरुआती दो साल के दौरान सागौन की खेती के बीच में अंतर फसल उगाई जाती है खासकर वहां जहां कृषि योग्य भूमि है। एक बार जब भूमि को पट्टे पर दे दिया जाता है तो पट्टेदार भूमि की सफाई, खूंटे जलाना और पौधारोपन का काम शुरु कर देता है। सागौन की खेती के बीच में आमतौर पर गेहूं, धान, मक्का, तिल और मिर्च के साथ-साथ सब्जी की खेती की जाती है। कुछ फसल जैसे कि गन्ना, केला, जूट, कपास, कद्दू, खीरा की खेती नहीं की जाती है।

सागौन की खेती में समस्याएं: निष्पत्रक और दीमक जैसे कीट बढ़ रहे सागौन के पौधे को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। सागौन के पौधे में आमतौर पर पॉलिपोरस जोनालिस लग जाता है जो पौधे की जड़ को गला देते हैं। गुलाबी रंग का फंगस पौधे को खोखला कर देते हैं। ओलिविया टेक्टोन और अनसिनुला टेक्टोन की वजह से पाउडर जैसे फफूंद पैदा हो जाते हैं जिससे असमय पत्ता झड़ने लगता है। इसके बाद पौधे के सुरक्षा के लिए रोगनिरोधी उपाय करना जरूरी हो जाता है। केलोट्रोपिस प्रोसेरा, डेट्यूरा मेटल और अजादिराचता इंडिका के ताजा पत्तों के रस इन रोगों से लड़ने में बेहद कारगर साबित होते हैं। जैविक और अकार्बनिक खाद के मुकाबले इससे हानिकारक कीट को अच्छी तरह से खत्म किया जाता है और साथ ही यह पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है।

नोट: पौधे में लगे मौजूदा कीट, बीमारी और उस पर नियंत्रण करने में कितना खर्च आयेगा इसके तकनीकी मूल्यांकन के लिए कृपया अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें।

सागौन की कटाई में ध्यान रखने वाली बातें-

- ▶काटे जाने वाले पेड़ पर चिन्ह लगाएं और सीरियल नंबर लिखें
- ▶क्षेत्रीय वन अधिकारी के पास इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराएं
- ▶क्षेत्रीय वन विभाग जांच के लिए अपने अधिकारी भेजकर रिपोर्ट तैयार करवाएगा
- ▶काट-छांट या कटाई के बारे में स्थानीय वन अधिकारी को रिपोर्ट भेजना
- ▶अनुमति मिलने के बाद काट-छांट या कटाई की प्रक्रिया शुरु की जाती है

सागौन की पैदावार: 14 साल के दौरान एक सागौन का पेड़ 10 से 15 क्यूबिक फीट लकड़ी देता है। सागौन का मुख्य तना आमतौर पर 25 से 30 फीट ऊंचा होता है और करीब 35 से 45 इंच मोटा होता है। एक एकड़ में उन्नत किस्म के करीब 400 सागौन का पेड़ पैदा होता है। इसके लिए पौधारोपन के दौरान 9/12 फीट का अंतराल रखना जरूरी होता है।

मिर्च की खेती से किसानों के जीवन में मिठास

बाराबंकी/सोनभद्र/चित्रकूट (विसं)। प्रदेश के कई जिलों के किसान मिर्च की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यहां पैदा होने वाली मिर्च सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच रही है। बाराबंकी जिले के बेलहरा ब्लॉक के दर्जनों गाँवों में बड़ी मात्रा में मिर्च की खेती होने लगी है। चिरैया गाँव के रहने वाले किसान सुरेश कुमार बताते है, पिछले वर्ष यहां के कई किसानों ने मिर्च की खेती की शुरुआत की है। इस खेती में अच्छा मुनाफा होने के कारण किसानो का रुझान मिर्च की खेती के तरफ बढ़ गया है। मिर्च की खेती करनी काफी आसान है। मिर्च की फ़सल में 10 से 15 दिनों के बीच पानी लगाया जाता है। यदि मौसम गर्म रहता है तो छह से आठ दिन में ही पानी लगाने की जरुरत पड़ जाती है। सोनभद्र जिले में हरी मिर्च की खेती भी बड़े पैमाने में हो रही है। देश के दूसरे हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी यहां की मिर्च का निर्यात होती है। जिला मुख्यालय से लगभग 20 किमी दूर धोरावल ब्लॉक में किसान मिर्च की खेती अधिक मात्रा में कर रहे हैं। बकौली गाँव के रहने वाले गजेंद्र बहादुर सिंह बताते हैं, 'मैंने पिछले वर्ष भी मिर्च की खेती की थी जिससे काफी मुनाफा हुआ था। इस वर्ष भी मैंने तीन एकड़ में मिर्च की खेती की है। मिर्च की पैदावार हमारे सोनभद्र में अच्छी हो रही है। हम लोग मिर्च को दूसरे प्रदेशों में भी भेजते हैं।' सोनभद्र के घोरावल, करमा, राबर्ट्सगंज, दुद्धी क्षेत्र में किसानों ने पारंपरिक खेती का ढर्रा बदलते हुए अब हरी मिर्च की खेती शुरू कर दी है। इन क्षेत्रों में हरी मिर्च के साथ-साथ कश्मीरी मिर्च की भी खेती की जा रही है। शुरुआत में मिर्च की पौध लगाने के बाद काफी बारिश हुई जिससे फसल को काफी नुकसान हुआ लेकिन अब मौसम अनुकूल होने के कारण फसल की पैदावार अच्छी हो गई है। जो बाजारों में बिकने के लिए जा रही है। देश के कई राज्यों के साथ-साथ बांग्लादेश के व्यापारी भी हरी मिर्च का व्यापार कर रहे हैं।

सूचना

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में समाविष्ट सभी बातों की जांच-परख कर पाना संभव नहीं है विज्ञापनों में अपने उत्पादनों अथवा अपनी सेवाओं के बारे में विज्ञापनदाता जो दावे करते हैं, सृष्टि एग्रो समाचार पत्र उसकी कोई गारंटी नहीं लेता।

विज्ञापनों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता द्वारा नहीं होती है तो उसके लिए पाक्षिक सृष्टि एग्रो समाचार पत्र समूह के मुद्रक, सम्पादक, प्रकाशक व मालिक किसी भी रूप में जवाबदेह नहीं होंगे, कृपया इसे ध्यान में रखें। अतः हम पाठकों से अनुरोध करते हैं विज्ञापन में उल्लेखित बातों के संदर्भ में कोई भी करार करने से पूर्व उसके बारे में आवश्यक छानबीन कर लें।

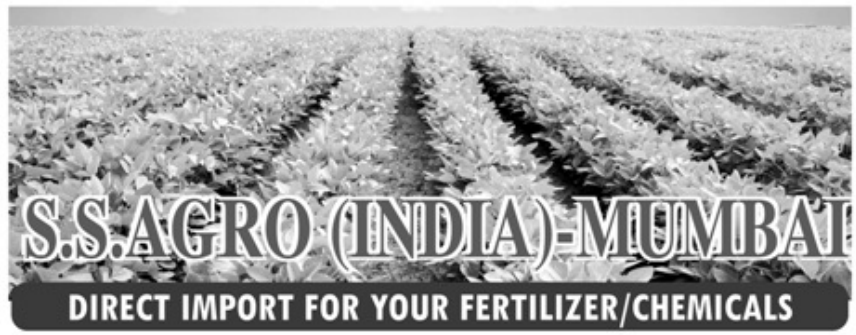

DIRECT IMPORT FOR YOUR FERTILIZER/CHEMICALS

- ☐ ZINK EDTA/COPPER
- ☐ EDTA/FF/EDTA
- ☐ 100% WATER SOLUBLE
- ☐ FERTILIZER (NPK)
- ☐ HUMIC ACID
- ☐ SEAWEED EXTRACT
- ☐ AMINO ACID
- ☐ POTASSIUM HUMATE
- ☐ FULVIC ACID
- ☐ EDDHA
- ☐ NATCA
- ☐ BRASSINOLIDE
- ☐ DAP
- ☐ SODA ASH
- ☐ SODIUM SULPHIDE
- ☐ AMONIUM CLORIDE
- ☐ SODIUM BICARBONATE
- ☐ CALCIUM CARBIDE
- ☐ PHOSPHORIC ACID
- ☐ TRI SODIUM PHOSPHATE
- ☐ CITRIC ACID
- ☐ STPP

ALL KIND OF INORGANIC

ORGANIC CHEMICALS

CONTACT NO. 022-6710-3722

आयातित गेहूं पर शिकंजे की तैयारी

सुरेश शर्मा

मुंबई । धुएं द्वारा कीटनाशक प्रक्रिया (फ्यूमिगेशन) अपनाए बिना गेहूं के आयात पर सरकारी नियम के तहत रोक के बावजूद भारत में इसका प्रवेश और सेवन लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह देखते हुए इस नियम में 31 मार्च से और ज्यादा सख्ती की जा रही है। लेकिन कुछ आयातकों ने धुएं द्वारा कीटनाशक प्रक्रिया के नकली प्रमाण-पत्रों के जरिये गेहूं भारत में लाने का तरीका निकाल लिया है। नियमों के तहत भारत में गेहूं के आयात के लिए उसी बंदरगाह पर हो मिथाइल ब्रोमाइड के धुएं से कीटनाशक प्रक्रिया अपनायी गई होनी चाहिए जहां से उसे भेजा गया हो। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसी खेपों के लिए भारतीय बंदरगाहों पर धुएं से कीटनाशक प्रक्रिया अपनाई जाती है। 31 मार्च से यह प्रक्रिया खेप भेजे जाने वाले बंदरगाहों पर ही पूरी की जाएगी। व्यापारियों ने कहा कि कुछ वैश्विक कंपनियों ने आयातकों के साथ सांठगांठ करके जाली प्रमाण-पत्रों के जरिये यह दिखाया था कि बंदरगाह से रवाना होने के बाद जहाजों को धुएं से कीट रहित कर लिया गया था। इससे 2016-17 के दौरान पिछले 10 सालों में सर्वाधिक 50.5 लाख टन के आयात के बीच धुएं से कीटनाशक प्रक्रिया के बिना ही कई टन गेहूं भारत में आने की आशंका है। भारतीय नियमों के अनुसार अगर आयात वाली कृषि जिंसों को स्रोत वाले स्थान पर ही धुएं से कीट रहित नहीं किया जाता है तो 75 डॉलर के सामान्य शुल्क की तुलना में प्रति टन 375 डॉलर रुपये का जुर्माना देकर इस प्रक्रिया को भारतीय तटों पर किया जा सकता है। भारत में उपस्थित अनाज व्यापार की बहुराष्ट्रीय कंपनी के एक प्रतिनिधि ने कहा कि 50,000 टन लाने वाले एक जहाज को प्रति टन 300 डॉलर का जुर्माना देते हुए 1.5-2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। यह देखते हुए कि आयात अनुबंध पहले ही किया जा चुका है, 31 मार्च से नये नियमों के तहत कुछ राहत मिल सकती है।

गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है सरकार- पासवान

नई दिल्ली। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान ने कहा कि चालू वर्ष में रिकॉर्ड उत्पादन होने के अनुमानों के बीच किसानों को सुरक्षित करने के लिए सरकार गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी को लगाने के बारे में विचार कर सकती है। सरकार ने गेहूं की घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा कीमतों को कम रखने के लिए हाल ही में गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था। पासवान ने कहा कि गेहूं की नई फसल अगले महीने से बाजार में आना शुरू होगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस अनाज को खरीदने के लिए पर्याप्त इंतजाम कर रही है तथा वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) हासिल हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाएगी। जिस तरह से इस सरकार ने दलहनों के मामले में उपाय किये हैं और किसानों को बेहतर एमएसपी प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से गेहूं उगाने वाले किसानों के लिए हर संभव उपाय किये जाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने के बारे में विचार किया जा सकता है।

मुंबई के महापौर का चुनाव आठ मार्च को

मुंबई (कासं)। मुंबई के अगले महापौर का चुनाव आठ मार्च को नए सदन की पहली बैठक के दिन होगा। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि इस पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख चार मार्च है और चुनाव आठ मार्च को दोपहर में होगा। बीएमसी में चुनाव पश्चात गठबंधन का कोई संकेत नहीं दिखने के बीच यह देखा जाना अभी बाकी है कि राजनीतिक दल महापौर चुनाव के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। चुनाव में खंडित जनादेश आया था। नया घटनाक्रम इन खबरों के बीच आया है कि इस नगर निकाय में दो मुख्य दलों- शिवसेना और भाजपा में नव निर्वाचित सदन की पहली बैठक की तारीख को लेकर अलग अलग राय थी। एक बीएमसी अधिकारी ने बताया कि निगम आयुक्त ने आठ मार्च का दिन तय किया है जो वर्तमान सदन का आखिरी दिन है। निगम आयुक्त ही नए सदन की पहली बैठक बुलाते हैं जिस दौरान महापौर का चुनाव होता है। हाल के बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने 84 सीटें और भाजपा ने 82 सीटें जीती थीं। कांग्रेस 31 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर चली गई, राकांपा को नौ और राजठाकरे के मनसे को सात सीटें मिलीं।

प्याज किसान रुआंसा व्यापारियों को मुनाफा

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र के नासिक जिले के लासलगांव में ज्यादातर किसानों की जहां प्याज उत्पादन की लागत भी नहीं निकल पा रही है, वहीं प्याज व्यापारियों ने उत्तर भारत में खासकर पंजाब में प्याज ले जाकर बेचने का मौका तलाश लिया है। एशिया में प्याज के सबसे बड़े हाजिर बाजार लासलगांव मंडी में प्याज के दाम 3.50 रुपये से छह रुपये प्रति किलोग्राम के बीच चल रहे थे। यह कीमत उत्पादन की अनुमानित लागत पांच रुपये प्रति किलोग्राम से काफी कम है। नासिक में अधिकांश किसान अपनी प्याज फसल पर घाटा झेल रहे है। इस साल जबरदस्त उपज की वजह से प्याज के दाम प्रति किलोग्राम दो रुपये तक यानी 29 प्रतिशत तक गिर चुके हैं। लासलगांव में आवक पिछले साल के 3,425.9 टन के मुकाबले बढ़कर 4,366.5 टन पहुंच गई।

व्यापारी लासलगांव से प्याज पंजाब और उत्तर प्रदेश ले जा रहे हैं जहां यह 11-13 रुपये के बीच बेचा जा रहा है। लासलगांव में चार रुपये प्रति किलोग्राम प्याज खरीदकर और श्रम व परिवहन की अतिरिक्त लागत के 2.5 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम मिलाकर कोई व्यापारी 5 से 7 रुपये कमा सकता है।

UDIT OVERSEAS PVT. LTD.

N.P.K. 100%WATER SOLUBLE FERTILIZER
- 19.19.19.
- 13.0.45(POTASSIUM NITRATE)
- 12.61.00 (MAP)
- 0.50.34 (MKP)
- 0.0.50 (SOP)
- CALCIUM NITRATE
- SRUSHTI HIZINC (MICRONUTRIENT MIXTURE)
- ZINC EDTA 12%
- ZINC SULPHATE 33%
- FERROUS EDTA 12%
- ZINC 21%
- FERROUS 19%
- MAGNESIUM
- BORON 20%
- COPPER SULPHATE 24%
- SULPHUR 90% WG

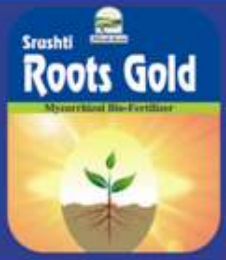

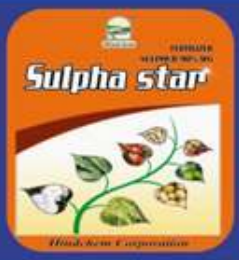

BIO FERTILIZERS
- MYCORRHIZA (ROOTS GOLD)
- AZOTOBACTOR
- RHIZOBIUM
- AZOSPIRILLUM
- PHOSPHATIC SOLUBILISING BACTERIA (PHOS UP)
- POTTASIUM MOBILIZING (POTA RISE)

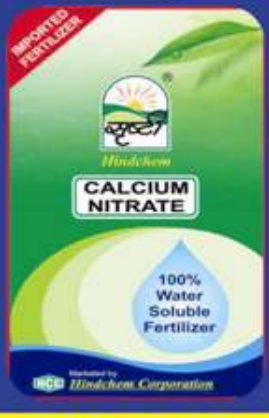

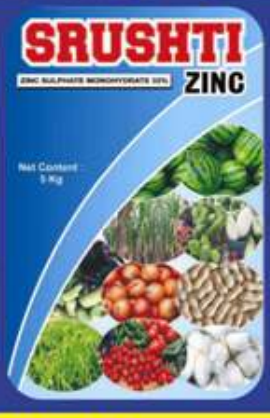

WELCOME INQUIRY Contact : 7728897567

137, Industrial Area Dehra, Tehsil Chomu, Dist, Jaipur

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - सुरेश जी. शर्मा की ओर से सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-63 से मुद्रित किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड (प), मुंबई-400064 यहां से प्रकाशित किया। सम्पादक : सुरेश जी. शर्मा, Contace Detail : Tel. 022-66998360/61, Fax : 022-66450908
E-mail : info@srushtiagronews.com, website : www.srushtiagronews.com RNI No. MAHHIN/2013/49425